जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

ARBIT

Celebrating with a New Port Galathea Bay

The coast was infested with crocodiles, and the *jungles* with snakes. Men had to be deputed with arms for protection.

World Wildlife Conservation Day

Dedicated efforts to protect our planet's incredible creatures and their habitats, ensuring that future generations get to share in the wonder of nature.

मुख्यमंत्री की दौड़ में देवेन्द्र फड़नवीस बहुत पीछे रह गये!

मोदी व शाह, दोनों फड़नवीस को मु.मंत्री बनाने के पक्ष में नहीं

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- आर.एस.एस., जो अब तक फड़नवीस को मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम में सबसे ज्यादा सक्रिय थी, अब कुछ शान्त सी हो गई है, क्योंकि संघ अभी मोदी शाह द्वय से खुली अदावत करने के पक्ष में नहीं लगता।
- अब प्रबल सम्भावना है, कि, महाराष्ट्र का नया मु.मंत्री भाजपा का कोई मराठा नेता होगा। तथा शाह उसके नाम पर मतैक्यता बनाने में जुटे हैं।
- वैसे अमित शाह की पसन्द तावड़े हैं, जो चर्चाओं के अनुसार, मतदान से पूर्व बहुत सारे ''कैश'' के साथ पकड़े गये थे।
- अतः सम्भावना है कि पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही, समय पर घोषणा हो जायेगी। हालांकि, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तबियत खराब होने की वजह से अस्पताल में हैं। जिज्ञासा केवल इतनी सी है, एकनाथ शिंदे की क्या राय रहती है, वे अंततोगत्वा, उपमुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लेंगे, या केन्द्र सरकार में शामिल होने के लिए दिल्ली जायेंगे, या राजनीति से ''सन्यास'' ले लेंगे।

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर। महाराष्ट्र सरकार की गुत्थी लगातार गुत्थी बनी हुई है।

अब यह बात स्पष्ट रुप से उभरकर सामने आ गई है कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में देवेन्द्र फड़नवीस काफी पीछे रह गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह दोनों ही फड़नवीस के पक्ष में नहीं हैं।

सूत्रों का कहना है कि आर.एस. एस., जो फड़नवीस का समर्थन कर रहा था, कुछ समय से मौन है, क्योंकि वह अभी मोदी और शाह से टकराव नहीं चाहता है।

पता चला है कि शपथ ग्रहण निर्धारित समय पर ही होगा, हालांकि शिवसेना के नेता व निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बीमार हैं और अस्पताल में हैं।

नया मुख्यमंत्री भाजपा का मराठा नेता होगा और अमित शाह अपनी पसंद के प्रत्याशी के लिए आम सहमति बनाने में रात दिन एक कर रहे हैं।

अभी तक किसी नाम का उल्लेख नहीं हुआ है, पर यह स्पष्ट है कि नाम की घोषणा में देरी इसीलिए की जा रही है, क्योंकि वे फड़नवीस को इस दौड़ से ही हटा देना चाहते हैं और अपनी पसंद के प्रत्याशी पर आम सहमति बनाना चाहते हैं। अमित शाह के प्रमुख प्रत्याशी हैं, तावडे, जो बहुत सारी नकद राशि के साथ पकड़े गए थे।

सूत्रों का कहना है कि अमित शाह तावडे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं।

एक प्रमुख प्रश्न यह है कि अब एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? क्या वे उपमुख्यमंत्री का पद स्वीकार करेंगे या फिर केन्द्र में मंत्री बनेंगे या एकान्तवास में चले जाएंगे।

भर्ती के एक साल बाद पी.टी.आई. की जाँच क्यों-हाईकोर्ट

जयपुर, 3 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पी.टी.आई. भर्ती-2022 में नियुक्ति के बाद एक साल से ज्यादा समय से नौकरी करने के बाद, भर्ती एजेंसी की ओर से एस.ओ.जी. के जरिए जांच कराने के मामले में शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी व सचिव कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश ममता जाट की याचिका पर दिए।

- अदालत ने शिक्षा सचिव, माध्यमिक निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी व सचिव कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने पी.टी.आई. भर्ती-2022 के लिए 16 जून को भर्ती विज्ञापन जारी किया था। इसके तहत ही बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया पूरी की। वहीं, इसमें दो बार जांच करने के बाद याचिकाकर्ता को पी.टी.आई. के पद पर नियुक्ति दी गई। इसके बाद चयन बोर्ड ने एस.ओ.जी. से अभ्यर्थियों की डिग्री की जांच कराई, जिसमें एस.ओ.जी. ने माना कि याचिकाकर्ता की ओर से ओ.पी.जी.एस. यूनिवर्सिटी से प्राप्त की गई डिग्री नियमानुसार सही नहीं है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अन्ततोगत्वा संसद पटरी पर लौटी

कांग्रेस की पहल पर सत्तापक्ष और विपक्ष का गतिरोध समाप्त हुआ

-जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- लोकसभा में अवश्य उस समय विपक्ष ने वॉक आउट किया, जब विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत और चीन के बीच हुई संधि के बारे में बताना शुरू किया।
- सपा चीफ अखिलेश यादव ने लोकसभा में और उनके चाचा रामगोपाल यादव ने राज्यसभा में संभल हिंसा का मुद्दा उठाया और यू.पी. सरकार पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया।
- तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय तथा कांग्रेस सांसद, के. सुरेश ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा पर चिंता जताई।
- संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवम्बर को शुरू हुआ था और 20 दिसम्बर तक चलेगा।

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर। सरकार और विपक्ष के बीच एक सप्ताह के लम्बे चले गतिरोध के बाद मंगलवार को संसद फिर पटरी पर आ गई। इसका श्रेय कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस की पहल पर लोकसभा स्पीकर ओम बिडला की अध्यक्षता में दोनों पक्षों के सदस्यों की मीटिंग हुई और लोकसभा व राज्य सभा में दो-दो दिन संविधान पर चर्चा के लिए सहमति बनी।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य सभा के सभापति तथा राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिख कर कहा कि भारतीय संविधान की 75 वीं वर्षगांठ पर दोनों सदनों में संविधान पर चर्चा कराई जाए। हालांकि 26 नवम्बर को पुरानी संसद के केन्द्रीय कक्ष में संसद की संयुक्त बैठक में चर्चा हो चुकी है।

विपक्ष ने लोकसभा से तब बहिर्गमन किया, जब विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने बैठक की शुरूआत में भारत व चीन के बीच हुई संधि का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि भारत और चीन के संबंध सुधरे हैं। उन्होंने बताया कि चीन ने कई जगहों पर भारी सेना तैनात कर दी थी। उन्होंने चीन को माकूल जवाब देने के लिए भारतीय सेना की तारीफ की।

सपा नेता अखिलेश यादव ने लोकसभा में सम्भल हिंसा का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि यू.पी. सरकार ने हिंसा करवाई है। राज्य सभा में यही मुद्दा अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव ने उठाया।

अखिलेश ने कहा, ''जो घटना सम्भल में घटी, वह एक सुनियोजित षडयन्त्र है तथा भाईचारे की हत्या कर दी गई है। चर्चा है कि भाजपा और उसके मित्र दलों द्वारा पूरे देश में खुदाई करवाई जाएगी, यह देश के भाईचारे को नष्ट कर देगी''। रामगोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश के इस नगर में पुलिस की तैनाती तथा पुलिस द्वारा पाँच लोगों को मार डालने तथा 20 लोगों को घायल कर देने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जो लोग पकड़े गये थे, उन्हें बुरी तरह पीटा गया।

संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवम्बर को शुरू हुआ था तथा 20 दिसम्बर तक चलेगा। कांग्रेस सांसद

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

फ्रांस, अब यूरोप में ब्रिटेन का स्थान लेने की पूरी कोशिश में

यह स्थान अब तक, ब्रिटेन के लिए आरक्षित था

- अंजन रॉय -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

- फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रां ने पेरिस के एतिहासिक चर्च नॉटरडैम, जो पांच साल पहले आग में जल कर लगभग पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया था, का पुनर्निर्माण (रेस्टोरैशन) करके, एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया है, और समारोह में राष्ट्रपति ट्रम्प को मुख्य अतिथि बनाया गया है।
- इस समय जर्मनी की लम्बे समय तक चांसलर रहीं, एंजिला मार्केल, विवादित व्यक्ति हो गई हैं। जर्मनी के सभी न्यूक्लियर बिजली घर बन्द करके, देश को रूस से आने वाली सस्ती नैचुरल गैस पर निर्भर बनाने से तथा जर्मनी में बहुत भारी संख्या में सीरिया के लोगों को नागरिकता प्रदान करके, देश में एक बड़ा हंगामा खड़ा करने के कारण।
- अतः फ्रांस के लिए बहुत सही समय है यूरोप में अमेरिका का ''बैस्ट फ्रैन्ड'' बनने के लिए।
- ट्रम्प भी फ्रांस की इस कोशिश से नाखुश नहीं हैं। इसका इज़हार ट्रम्प ने फ्रांस में अपने नजदीकी रिश्तेदार को अमेरिका का राजदूत बनाकर भेजकर किया।
- फ्रांस की, अमेरिका के नज़दीक आने की मुहिम सफल होती नज़र आ रही है।

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर। विक्टर ह्यूगो की कहानी ''हंचबैक ऑफ नॉट्र डाम'' फ्रांस का प्रतीक थी। जिसका मुख्य किरदार हंचबैक गिरिजाघर की बड़ी-बड़ी घंटियों पर झूलता है, ताकि घंटियों की आवाज़ ''रोशनी के शहर'' पेरिस में पहुँच सके।

अब, एक विनाशकारी आग से लगभग नष्ट हो जाने के पांच साल बाद नॉट्र डाम के पुनर्निर्मित गिरिजाघर का उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रां 4 दिसम्बर को करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पुनःस्थापित इस शानदार गिरिजाघर को यूरोपीय कूटनीति के केन्द्र में रखने का फैसला किया है।

मैक्रां ने इस कार्यक्रम को, हाल के समय की सबसे बड़ी कूटनीतिक क्रांति का रूप दिया है। उन्होंने अमेरिका के भावी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प को चर्च के शानदार पुनः उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया है। ट्रम्प, जिन्हें जीवन में किसी भी अन्य चीज़ से ज्यादा चापलूसी और चमकदार रोशनी पसंद है, नॉट्र डाम के भव्य पुनः उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने को लेकर अति प्रसन्न हैं।

यह अटलांटिक पार के देशों के बदलते संबंधों और पश्चिमी देशों के गठबंधन के महत्व को दर्शाता है। कुछ समय पहले तक, ग्रेट ब्रिटेन के अमेरिका के साथ तथाकथित ''विशेष संबंध'' थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तथा युद्ध के बाद यूरोप भर में हो रहे पुनर्निर्माण के समय शान के साथ दर्शाए गए थे।

अब, फ्रांस यूरोप में अमेरिका के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अपराध साबित नहीं हुआः मालपुरा दंगे के 5 आरोपी बरी

जयपुर, 3 दिसंबर। सांप्रदायिक दंगा मामलों की विशेष अदालत ने 24 साल पहले टोंक जिले के मालपुरा में सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुई हत्या के मामले में पांच आरोपियों अब्दुल वहाब, मोहम्मद हसीब, आसिफ, फिरोज अहमद और उमर को बरी कर दिया है। पीठासीन अधिकारी श्वेता गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों पर हत्या का आरोप साबित नहीं कर सका है। ऐसे में आरोपियों को दोषमुक्त किया जाता है।

- पीठासीन अधिकारी ने कहा, अभियोजन पक्ष आरोपियों पर हत्या का आरोप सिद्ध नहीं कर पाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 10 जुलाई, 2000 को मालपुरा में दो संप्रदायों के बीच दंगा हुआ था। इस दौरान, चुंगी नाके के पास कैलाश माली की हत्या कर दी गई थी। घटना को लेकर मृतक के बेटे मनोज ने दो दिन बाद रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसे जांच के लिए बाद में सी.आई.डी. सी.बी. को भेजा गया था। सी.आई.डी. सी.बी. ने मामले में जांच कर 9 अक्टूबर, 2000 को अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शौकत आलम व अन्य ने बताया कि मृतक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों को 22 साल बाद आवंटित होंगे मकान

अन्ततोगत्वा हाउसिंग बोर्ड के तीन कर्मचारियों को हाईकोर्ट से इंसाफ मिला

-यादवेंद्र शर्मा-

- हाउसिंग बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए 2002 में यह स्कीम निकाली थी, जिसमें इन तीन कर्मचारियों ने पंजीयन राशि जमा करवाई थी और हाउसिंग बोर्ड ने भी 2006 में प्रस्ताव पारित किया था कि पंजीयन राशि जमा कराने वालों को मकान आवंटित होगा, पर इन तीन कर्मचारियों को मकान आवंटन नहीं किया गया।
- इस मामले में हाउसिंग बोर्ड कई वर्ष तक इसलिये कोई आवंटन नहीं कर सका क्योंकि बोर्ड के अधिकारी इस स्कीम में उन कर्मचारियों को भी मकान आवंटन करने लगे थे जो प्रतिनियुक्ति पर हाऊसिंग बोर्ड में आये थे और बोर्ड में स्थाई नहीं हुए थे। इस पर 2007 में कोर्ट में मामला दर्ज किया गया था।
- हाउसिंग बोर्ड के वकील ने हाईकोर्ट में यह तर्क दिया कि उपरोक्त वर्णित विवाद के लंबित रहने के दौरान बोर्ड ने यह प्रस्ताव पास कर दिया था, कि प्लिंथ स्तर के मकानों का भविष्य में आवंटन नहीं करेगा। वकील का कहना था कि इस कारणवश बोर्ड ने इन तीन कर्मचारियों को आवंटन नहीं किया है। दूसरी ओर इन कर्मचारियों ने आवंटन के लिये मूल राशि जमा नहीं कराई थी। हाईकोर्ट ने इन दोनों तर्कों को खारिज कर दिया है।

जयपुर, 3 दिसम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आवासन बोर्ड की अपील को खारिज करते हुए आदेश दिये हैं कि उसके कर्मचारियों के लिये 2002 में लाई गई स्पेशल स्कीम के तहत तीन याचिकाकर्ता धर्मेंद्र, लूणकरण और संजय चौबीसा को स्कीम अनुसार प्रतापनगर में ''प्लिंथ'' स्तर के आवासों का आवंटन करें क्योंकि याचिकाकर्ता कर्मचारी ने उपयुक्त समय पर पंजीयन के लिये राशि जमा करा दी थी। मुख्य न्यायाधीश एम.एम.श्रीवास्तव और न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने इसी मामले में एकलपीठ द्वारा दिये गये आदेश में केवल इतना सा संशोधन किया है कि हाऊसिंग बोर्ड को 6 नवम्बर 2015 को लागू ''रेट'' के अनुसार मूल राशि (सीड मनी) मान्य होगी, एकलपीठ ने 2007 को हाऊसिंग बोर्ड को आवंटन करने के आदेश दिये थे। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुधांशु जोशी और पी.पी.माथुर पैरवी के लिये पेश हुए।

जिरह के दौरान अधिवक्ता सुधांशु जोशी ने अदालत को बताया कि यह स्कीम 2002 में लाई गई थी, और उनके मुवक्क्लि ने 2006 तक पंजीयन शुल्क पूरा दे दिया था। दूसरी ओर हाऊसिंग बोर्ड के वकील की ओर से कहा गया कि इन तीन कर्मचारियों ने लंबे समय तक आवास के आवंटन के लिये मूल राशि जमा नहीं कराई थी।

इस पर सुधांशु जोशी ने अदालत को बताया कि इस मामले में सीड मनी 2014 तक इसलिये अदा नहीं किया जा सका क्योंकि 50 घरों की यह स्कीम 2007 में हाईकोर्ट में एक विवाद में उलझी रही जिसका निस्तारण वर्ष 2015 में हुआ। उन्होंने अदालत को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह भव्य बनाने की तैयारी

मुंबई, 03 दिसंबर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। यहां महायुति की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। महायुति की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद पार्क में 5 दिसंबर को होने जा रहा है। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में कुल 70 से ज्यादा वी.वी.आई.पी. नेता शामिल होंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित कैबिनेट के कई

- प्रधानमंत्री, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नड्डा, गडकरी सहित सत्तर वी.आई.पी. समारोह में आयेंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रम्प ने ''ब्रिक्स देशों'' पर सौ प्रतिशत शुल्क लगाने की धमकी दी

अमेरिका ''ब्रिक्स देशों'' की, आपसी व अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लिए डॉलर का उपयोग न करने की चेष्टा से काफी क्षुब्ध है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- भारत, अमेरिका की इस नाराज़गी का समर्थन कर रहा है। क्योंकि भारत के अमेरिका से काफी सुविधाजनक व फायदे मंद सम्बंध हैं, और वह ''डॉलर विहीन'' अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्ष में है।
- ''ब्रिक्स देशों'' के समूह में रूस व चीन, डॉलर के बजाय किसी अन्य मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रबल समर्थक हैं। क्योंकि, अमेरिका ने रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद, रूस की अमेरिकी बैंक में मुद्रा आदि को फ्रीज़ कर दिया था, जिससे रूस को काफी दिक्कत आई थी, अपना तेल (ऑयल) अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेचने में।
- भारत का रुख है, व्यापार को राजनीतिक झगड़ों का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। व्यापार, आपसी सहूलियत पर आधारित होना चाहिए। और भारत डॉलर विरोधी मुहिम में शामिल नहीं है।

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा ब्रिक्स देशों की ग्लोबल रिज़र्व करैंसी के रुप में डॉलर्स पर निर्भरता कम करने के प्रयासों की आलोचना को भारत से समर्थन मिला है। डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश अर्थात ''डी-डॉलराइजेशन'' का सबसे मुख्य एवं मुखर समर्थक रुस है। रुस का मत है कि पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाली वित्तीय व्यवस्था को बाइपास करने का यही तरीका है।

ऑब्ज़र्वर रिसर्च पाउण्डेशन (ओ.आर.एफ.) में स्टडीज़ एण्ड फॉरैन पालिसी के वाइस प्रैसिडैंट हर्ष वी. पंत के अनुसार, ब्रिक्स देशों की कॉमन करैंसी पर रुस का समर्थन पश्चिमी देशों के प्रभाव से खुद को दूर करने का प्रयास है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अक्टूबर की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत का रुख स्पष्ट कर दिया था कि भारत डॉलर को निशाना बनाने या डॉलर पर निर्भरता कम करने की रणनीति का समर्थन नहीं करता है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि जिन देशों के पास डॉलर का अभाव है, उनके साथ ट्रेड के लिए भारत की रणनीति व्यवहारिक सोच पर आधारित है, न कि इसके पीछे कोई विचारधारा है। भारत ट्रेड के लिए एक प्रगतिशील सोच रखता है, डॉलर को कम नहीं करना चाहता है। जयशंकर के बयान का अर्थ है कि ऐसी कार्यवाही राजनैतिक रुप से प्रेरित नहीं है, बल्कि वैश्विक ट्रेड की वास्तविकताओं पर आधारित है, जहां कई बार लेन-देन में स्थानीय मुद्रा प्रयुक्त की जाती है। ब्रिक्स देशों के स्थानीय मुद्रा में ट्रेड पर जोर दिए जाने पर ट्रम्प ने सख्त प्रतिक्रिया दी और धमकी दी कि अगर उन्होंने डॉलर से दूरी बनाने की मुहिम जारी रखी तो उन पर शत प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि अमेरिका इस मसले पर कितना चिंतित है क्योंकि सैंट्रल बैंक्स के रिज़र्व मुद्रा कोष में अमेरिकन डॉलर गत दो दशकों में घटा है। इसकी शुरुआत यूरो से हुई और विकासशील देशों द्वारा आपसी ट्रेड स्थानीय मुद्रा में करने से इस प्रवृति को बढ़ावा मिला, जैसा भारत सहित कई देशों में देखा जाता है।

इन्टरनैशनल मॉनेटरी फंड (आई.एम.एफ.) के डेटा के अनुसार, 1999 से 2024 के बीच ग्लोबल रिज़र्व से डॉलर की मात्रा 71 प्रतिशत से हटकर 58 प्रतिशत रह गई, वहीं यूरो की हिस्सेदारी बढ़ी है।

पंत ने कहा कि भारत के पास ''डी-डॉलराइजेशन'' का कोई आर्थिक, रणनीतिक या राजनैतिक कारण नहीं है। भारत लंबे समय से अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी रहा है और ग्लोबल ट्रेड में डॉलर की स्थिरता व इस्तेमाल में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'कार्यस्थल व सार्वजनिक जगहों पर महिला टॉयलेट की व्यवस्था हो'

जयपुर, 3 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कार्यस्थल और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के लिए टॉयलेट की कमी और मौजूदा टॉयलेट की खराब हालतों पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में केन्द्र सरकार, मुख्य सचिव, प्रमुख नगरीय विकास सचिव और स्वायत्त शासन निदेशक को नोटिस जारी कर विभिन्न बिंदुओं पर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश इस संबंध में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिए। अदालत ने इन अधिकारियों से इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी भी पेश करने को कहा है। अदालत ने अधिवक्ता सुप्रिया

- हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर केन्द्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK